

92. आगामी वर्ष में 1 हजार राज्य स्तरीय एवं 5 हजार स्थानीय स्तर के गार्डों को प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिससे कि उन्हें गार्ड लाईसेंस प्रदान किये जा सकें।

### पांचवा संकल्प—शिक्षा का परिधान

प्रदेश के अच्छे कल के लिए हमें विद्यार्थियों को बेहतरीन शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करवाना होगा। अच्छी शिक्षा आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा सर्वश्रेष्ठ उपहार हो सकता है और ये ही हमारा 5वां संकल्प है।

#### शिक्षा:

93. शिक्षा से जुड़े सभी विभागों के लिए वर्ष 2020–21 में हमने कुल 39 हजार 524 करोड़ 27 लाख रुपये का प्रावधान किया है।

94. प्रदेश में 33 जिला मुख्यालयों पर महात्मा गांधी के नाम से English Medium राजकीय विद्यालयों का प्रयोग काफी सफल रहा है। राज्य के 301 शैक्षणिक ब्लॉक में से 134 ब्लॉक पर English Medium विवेकानन्द मॉडल स्कूल स्थापित हो चुके हैं। अतः अब, शेष 167 ब्लॉक में प्रत्येक में एक English Medium महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

95. Right to Education के तहत राज्य में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्राथमिक से लेकर सीनियर हायर सैकंडरी तक विद्यालयों का होना सुनिश्चित किया जा चुका है। इस संबंध में संभावित gap को भरने के लिए आवश्यकतानुसार उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं सीनियर हायर सैकंडरी विद्यालय खोले जाने प्रस्तावित हैं।

96. प्रदेश के 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय एवं 300 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विषय आवश्यकतानुसार खोले जायेंगे, जिन पर 25 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

97. एक सकारात्मक पहल करते हुए हमने यह निर्णय लिया है कि समस्त सरकारी विद्यालयों में शनिवार के दिन **No Bag Day** रहेगा और उस दिन कोई अध्यापन कार्य नहीं होगा। इस दिन अभिभावक-अध्यापक (Parent-Teacher) मीटिंग के अतिरिक्त साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, हैप्पीनेस थेरेपी, खेलकूद, व्यक्तित्व विकास, स्काउट, जीवनमूल्य एवं नैतिक शिक्षा, बालसभायें तथा भाषा एवं कौशल विकास एवं निरोगी राजस्थान के सूत्रों से संबंधित क्रियायें संपादित करवायी जायेंगी, जिनमें अध्यापकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जायेगा।

98. राज्य के शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर में अतिरिक्त कक्षा कक्ष, छात्रावास, बैडमिंटन कोर्ट, स्वीमिंगपूल, ऑडिटोरियम आदि सुविधायें विकसित की जायेंगी। इस हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाता है।

99. राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के लिए नये 'कम्प्यूटर शिक्षक कैंडर' का सृजन किया जाना प्रस्तावित है।

100. राज्य के 204 ब्लॉक में अभी 319 कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं, जिनमें 38 हजार 700 बालिकायें अध्ययनरत हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आगामी 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से 66 कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जायेगी। प्रथम चरण में 22 कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोले जायेंगे, जिनमें से 12 विद्यालय तलवाड़ा,

अर्थुना, गांगड़ तलाई एवं छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा, पाटोदी एवं शिव जिला बाड़मेर, गलियाकोट जिला डूंगरपुर, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़, कुरावड़, लसाड़िया, झल्लारा एवं ऋषभदेव जिला उदयपुर के अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स में खोले जायेंगे। शेष 10 विद्यालय मण्डरायल जिला करौली, धनाउ जिला बाड़मेर, बिदासर जिला चूरु, बिजोलिया जिला भीलवाड़ा, नोहर एवं भादरा जिला हनुमानगढ़, सुल्तानपुर जिला कोटा, बांदीकुई जिला दौसा, खानपुर जिला झालावाड़ तथा आमेर जिला जयपुर में खोले जायेंगे।

### उच्च एवं तकनीकी शिक्षा:

101. महाविद्यालयों में पढ़ रहे युवाओं में कौशल विकास हेतु Skill Enhancement & Employable Training (SEET) कार्यक्रम आरंभ किया जायेगा। इसमें राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) एवं राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से प्रति वर्ष 10 हजार विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

102. प्रदेश के महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को ऑफलाइन/ऑनलाइन वीडियो लेक्चर की सुविधा के लिए **राजीव गांधी ई-कन्टेन्ट बैंक** की स्थापना की जायेगी, जिसमें कॉलेज शिक्षकों द्वारा दिये गये लेक्चर को रिकॉर्ड किया जायेगा एवं इसके माध्यम से विद्यार्थियों को भविष्य में निरंतर क्वालिटी एजुकेशन मुहैया करवायी जाती रहेगी।

103. पिछले बजट में हमने राजकीय महाविद्यालय खोलने हेतु नीति बनाने की घोषणा की थी। यह नीति जारी की जा चुकी है। गत वर्ष घोषित